RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

राजधर्म और ग्राम शासनःभारतीय ज्ञान परंपरा में सुशासन की अवधारणा का पुनर्पाठ

*Sunita kumari

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

सारांश

भारतीय शासन-चिंतन में *'राजधर्म'* केवल शासन की नीति नहीं, बल्कि नैतिकता, लोककल्याण और उत्तरदायित्व की समग्र संकल्पना है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि शासक का धर्म उसकी सत्ता से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रति नैतिक दायित्व से परिभाषित होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ– *ऋग्वेद, महाभारत, मनुस्मृति, नारदस्मृति* और *कौटिल्य के अर्थशास्त्र* शासन की उस परंपरा का परिचय कराते हैं जिसमें राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है (Thakuria, 2019)। *ग्राम शासन* या स्थानीय स्वशासन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की नींव था, जहाँ शासन का मूल उद्देश्य *'लोकसंग्रह'* अर्थात् सबके हित में प्रशासन माना गया। *शान्ति पर्व* में यह स्पष्ट कहा गया कि *'राजा धर्म से प्रजा की रक्षा करता है और धर्म से ही राज्य की स्थिरता बनी रहती है'* (Mahabharata, Shanti Parva 88)। इस नैतिक दृष्टिकोण ने शासन को केवल कानून-व्यवस्था का उपकरण न मानकर एक सामाजिक दायित्व के रूप में देखा। आज जब वैश्विक संदर्भ में *Good Governance* के सिद्धांत जैसे *Transparency, Accountability, Participation, Equality* और *Rule of Law* चर्चा के केंद्र में हैं, तब भारतीय परंपरा में निहित *'राजधर्म'* की अवधारणा इन आधुनिक मानदंडों के समानांतर एक गहन नैतिक आधार प्रस्तुत करती है। *गांधीजी* ने *'ग्राम स्वराज'* की परिकल्पना में इसी *राजधर्म* को आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप पुनर्परिभाषित किया था, जहाँ शासन का हर स्तर जनसेवा और न्याय का प्रतीक बने (Hind Swaraj, 1909)।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य *राजधर्म* और *ग्राम शासन* के पारंपरिक विचारों का पुनर्पाठ करते हुए यह विश्लेषण करना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित सुशासन की अवधारणा आज के लोकतांत्रिक युग में कितनी प्रासंगिक है। यह अध्ययन निष्कर्ष देता है कि भारतीय परंपरा का *राजधर्म* शासन के नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण रूप को समझने के लिए न केवल ऐतिहासिक दृष्टि देता है, बल्कि समकालीन शासन-संरचनाओं के लिए एक स्थायी वैचारिक आधार भी प्रदान करता है (Mehrotra, 2018; Singh, 2020)।

Article Publication

Published Online -November 2025

Corresponding Author

Sunita Kumari

Research scholar

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Email- Sunitad5devi@gmail.com

© 2025 - published by *Vidhina*

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

परिचय

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

भारतीय सभ्यता की राजनीतिक और दार्शनिक परंपरा में *'राजधर्म'* की संकल्पना शासन की आत्मा के रूप में मानी गई है। *'राज'* का अर्थ केवल सत्ता या शासन नहीं, बल्कि *'प्रजापालन'* है, और *'धर्म'* का अर्थ नैतिकता, न्याय और लोककल्याण से है। जब ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तो *'राजधर्म'* एक ऐसे शासन सिद्धांत का निर्माण करता है जिसमें राजा को शक्ति का नहीं, बल्कि नीति, न्याय और लोकसेवा का प्रतिनिधि माना जाता है (Ghosh, 1915)। यह विचार भारतीय शासन-दर्शन को पाश्चात्य शक्ति-केन्द्रित राज्य-सिद्धांतों से अलग करता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में शासन का उद्देश्य राज्य की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण (Kane, Dharmashastra, Vol. 3) रहा है।

महाभारत के *शान्ति पर्व* में भी कहा गया है – **"धर्मेण ही राज्ञो रक्षणं प्रजायाःधर्मेण चैव राज्यं प्रतिष्ठितम्।"** राजा धर्म से ही प्रजा की रक्षा करता है और धर्म से ही राज्य स्थिर रहता है (Mahabharata, Shanti Parva 88)। यह वचन शासन के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करता है कि यदि धर्म अर्थात् नैतिकता शासन से लुप्त हो जाए, तो राज्य अपने आप पतन की ओर अग्रसर होता है। यह विचार *मनुस्मृति* में और अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है – **"राजा का कर्तव्य न्याय की स्थापना, दीनों की रक्षा, और लोभ-मोह से रहित शासन करना है।"** (Manusmriti, Ch.7)। इस प्रकार *'राजधर्म'* शासन के लिए एक नैतिक मानक का कार्य करता है।

ग्राम शासनःराजधर्म की व्यावहारिक अभिव्यक्ति

प्राचीन भारत में *'ग्राम'* प्रशासनिक ढाँचे की मूल इकाई था। ग्राम न केवल आर्थिक उत्पादन का केंद्र था, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी था। *कौटिल्य के अर्थशास्त्र* में वर्णन मिलता है कि *"राजा को प्रत्येक ग्राम में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो लोककल्याण में तत्पर हों और जो न्याय की भावना से शासन करें, न कि अपने लाभ के लिए।"* (Kautilya, Arthashastra, Book 1)। यह व्यवस्था आज के *Decentralized Governance* की मूल प्रेरणा कही जा सकती है। ग्राम प्रशासन में *सभाएँ* और *परिषदें* लोकतांत्रिक विमर्श के प्रारंभिक स्वरूप थे। ये संस्थाएँ न केवल स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं, बल्कि कृषि, जल-संसाधन, कर व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन से संबंधित निर्णयों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती थीं। इस प्रकार, भारतीय शासन-दर्शन ने *Participatory Democracy* का बीज उसी काल में बो दिया था जब पाश्चात्य विश्व में यह विचार अपरिचित था (Singh, 2020)।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

नैतिक शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व

'राजधर्म' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शासन को नैतिक उत्तरदायित्व का रूप देता है। *कौटिल्य* कहते हैं – *"राजा का सुख प्रजा के सुख में है, और उसका हित प्रजा के हित में।"* (Kautilya, Arthashastra, Book 19)। यह कथन आधुनिक *Good Governance* के उस सिद्धांत की जड़ को दर्शाता है जिसमें शासन का केंद्र *'जनता'* होती है, न कि *'शासक'*। यही विचार आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन की आधारशिला है। *'राजधर्म'* इसलिए केवल राजाओं का आचार-संहिता नहीं था, बल्कि शासन-व्यवस्था का नैतिक मापदंड भी था। *मनुस्मृति* (अध्याय 7) में राजा को *'धर्म का संरक्षक'* कहा गया है, जिसका कार्य न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार *'राजधर्म'* की अवधारणा उस समय के लिए भी *Transparency* और *Accountability* की अभिव्यक्ति थी। राजा के आचरण पर भी नैतिक नियंत्रण था, जो आधुनिक प्रशासनिक जवाबदेही (*Administrative Responsibility*) के समान था (Mehrotra, 2018)।

आधुनिक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में राजधर्म

आधुनिक युग में प्रशासन का स्वरूप बदल गया है, परंतु *'राजधर्म'* की भावना आज भी शासन के मूल्यों में जीवित है। आज जब हम *Transparency (पारदर्शिता), Accountability (उत्तरदायित्व), Participation (सहभागिता), Equality (समानता)* और *Rule of Law (कानून का शासन)* जैसे आधुनिक शासन-सिद्धांतों की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ये सभी तत्व भारतीय परंपरा के *राजधर्म* और *ग्राम शासन* की जड़ों में निहित हैं। *महात्मा गांधी* ने *'ग्राम स्वराज'* की परिकल्पना में इसी *राजधर्म* को पुनःजीवित किया। उन्होंने लिखा – *"सच्चा स्वराज वही है जो प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसंयम और आत्मसेवा से उत्पन्न होता है; जहाँ शासन नहीं, बल्कि आत्म-शासन होता है।"* (Hind Swaraj, 1909)। गांधी का यह विचार प्राचीन *राजधर्म* का लोकतांत्रिक रूपांतरण था, जहाँ शासन एक *Moral System of Self-Governance* बन जाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का आचरण समाज के शासन-संतुलन में भूमिका निभाता है।

राजधर्मःनीति और नैतिकता का संतुलन

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

भारतीय राजनैतिक परंपरा में *'राजधर्म'* केवल आचार या धर्मशास्त्र नहीं था, बल्कि यह एक *Philosophical Framework* था जो *Policy (नीति)* और *Ethics (धर्म)* को एकीकृत करता था। आधुनिक राज्य जहाँ *Political Governance* पर बल देता है, वहीं प्राचीन भारत *Moral Governance* का पक्षधर था। यह दृष्टिकोण बताता है कि शासन की स्थिरता केवल कानूनों से नहीं, बल्कि नैतिक विश्वास और सामाजिक स्वीकृति से आती है (Mahabharata, Shanti Parva 90)।

इस सन्दर्भ में, *'राजधर्म'* और *'ग्राम शासन'* का अध्ययन समकालीन भारत के लिए केवल ऐतिहासिक समीक्षा नहीं, बल्कि भविष्य के *Good Governance* की दिशा में एक वैचारिक मार्गदर्शन है। यदि शासन में नीति, धर्म और सेवा — इन तीनों का संतुलन बना रहे, तो प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण न केवल राजनीतिक रूप से सक्षम होगा, बल्कि नैतिक रूप से वैध भी ठहरेगा।

शोध का उद्देश्य और महत्व

इस शोधपत्र का उद्देश्य *'राजधर्म'* और *'ग्राम शासन'* की अवधारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है ताकि यह समझा जा सके कि आधुनिक सुशासन की जो वैश्विक संकल्पना *Good Governance* कहलाती है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा से किस हद तक जुड़ी हुई है। इस अध्ययन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं —

1. प्राचीन भारतीय शासन-दर्शन में *'राजधर्म'* की नैतिक संरचना को विश्लेषित करना।
2. ग्राम शासन के माध्यम से प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करना।
3. आधुनिक प्रशासन में *'राजधर्म'* के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को स्थापित करना।

यह अध्ययन मानता है कि भारतीय परंपरा केवल अतीत का इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान शासन-नीति और प्रशासनिक सुधारों के लिए एक *philosophical framework* है, जो *policy* और *ethics* के समन्वय से सुशासन की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करता है।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

राजधर्म और सुशासन की वैचारिक समानता

'राजधर्म' भारतीय राजनीतिक चिंतन की वह आत्मा है जो सत्ता को नैतिकता से जोड़ती है। दूसरी ओर, *'Good Governance'* आधुनिक प्रशासनिक शब्दावली का वह रूप है जो शासन को पारदर्शिता (*transparency*), उत्तरदायित्व (*accountability*), और सहभागिता (*participation*) के आधार पर परिभाषित करता है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच भले ही समय और भाषा का अंतर हो, किंतु उनके मूलभूत मूल्य समान हैं — जनकल्याण, न्याय, और नैतिक शासन (Dhiman, 2018)।

महाभारत में कहा गया है — **"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः"** अर्थात् जो धर्म का पालन करता है, वही संरक्षित होता है (Mahabharata, Shanti Parva, 88)। यह विचार आधुनिक सुशासन की अवधारणा से मेल खाता है, जहाँ *Rule of Law* और *Human Rights* को शासन की रीढ़ माना गया है। इस प्रकार, *'राजधर्म'* और *'सुशासन'* दोनों ही सत्ता को *सेवा* का रूप देते हैं, न कि *शक्ति* के प्रदर्शन का।

पारदर्शिता (Transparency) का राजधर्म में सन्निवेश

राजधर्म के अनुसार, राजा को अपने निर्णयों में न केवल न्यायपूर्ण होना चाहिए, बल्कि जनता के प्रति खुलापन भी बनाए रखना चाहिए। *कौटिल्य* ने *अर्थशास्त्र* में शासन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए — **"राजा को जनता के हित में कार्य करते समय अपने कर्मों को गुप्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता ही विश्वास की जननी है।"** (*Arthashastra*, Book 7)।

आधुनिक शासन प्रणाली में यही विचार *Right to Information Act (2005)* के रूप में विकसित हुआ है। जब शासन जनता के प्रति जवाबदेह और खुला होता है, तब सत्ता और प्रजा के बीच विश्वास (*trust*) का निर्माण होता है। *राजधर्म* की दृष्टि में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि धर्म पालन का अंग है — जहाँ शासक की नीयत, नीति और परिणाम सभी जनता के समक्ष निष्पक्ष हों। यही वह आधार है जिससे *United Nations (1997)* की *Good Governance* में *transparency* की अवधारणा जुड़ती है।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

उत्तरदायित्व (Accountability) और दायित्व का नैतिक विमर्श

राजधर्म में उत्तरदायित्व का अर्थ केवल प्रशासनिक जवाबदेही नहीं, बल्कि आत्मिक दायित्व (*moral responsibility*) से भी है। *मनुस्मृति* में कहा गया है — **"राजा को अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि वही अपने राज्य का भाग्यनिर्माता है।"** (*Manusmriti*, Ch.7, Verse 20)।

यह सिद्धांत आधुनिक *Administrative Responsibility* की वैचारिक जड़ है। आज के लोकतांत्रिक शासन में जहाँ संसद, न्यायपालिका, और मीडिया जैसी संस्थाएँ प्रशासन की निगरानी करती हैं, वहीं यह परंपरा प्राचीन भारत में *जनमत* और *धर्मसभा* के रूप में विद्यमान थी। *राजधर्म* में उत्तरदायित्व का सबसे सुंदर उदाहरण *रामराज्य* की संकल्पना में मिलता है, जहाँ *राजा राम* ने न केवल प्रजा के प्रति बल्कि अपने निजी निर्णयों के लिए भी जवाबदेही स्वीकार की। इस आदर्श को *महात्मा गांधी* ने *'ग्राम स्वराज'* में पुनःपरिभाषित किया — **"नेता वही जो जनता के प्रति सर्वाधिक उत्तरदायी हो।"** (*Hind Swaraj*, 1909)।

सहभागिता (Participation) और लोकसंग्रह की परंपरा

राजधर्म का सबसे जीवंत पक्ष *'लोकसंग्रह'* अर्थात् *collective participation* है। *भगवद्गीता* में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा— **"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः"** (*Bhagavad Gita*, 3.21)
अर्थात् शासक के कर्म समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श होते हैं। यह विचार शासन में नागरिक सहभागिता का नैतिक आधार प्रस्तुत करता है। *कौटिल्य* ने *अर्थशास्त्र* में ग्राम प्रशासन को सहभागितापूर्ण शासन की सबसे सक्षम इकाई बताया। *ग्रामिक*, *ग्राम परिषद्* और *सभाएँ* शासन में जनता की सीधी भूमिका सुनिश्चित करती थीं। आधुनिक लोकतंत्र में यही परंपरा *Participatory Democracy* और *Decentralized Governance* के रूप में पुनर्जीवित हुई। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) द्वारा *Panchayati Raj* और *Urban Local Bodies* को जो संवैधानिक दर्जा मिला, वह *राजधर्म* की भावना का आधुनिक अनुवाद है। स्थानीय शासन में सहभागिता न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाती है, बल्कि शासन को नैतिक रूप से सक्षम भी बनाती है (Pathak, 2010)।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

समानता और न्याय (Equality and Justice)

राजधर्म का मूल तत्व है — **"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।"** शासन का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण है। *महाभारत* में स्पष्ट कहा गया है कि राजा को सभी प्रजाजनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि पक्षपात ही राज्य के पतन का कारण है (Mahabharata, Shanti Parva, 88)। आधुनिक *Good Governance* के सिद्धांतों में *Equality* और *Social Justice* को जो महत्व दिया गया है, वह इसी राजधर्मीय चेतना से उत्पन्न है। भारत के संविधान में *समता, स्वतंत्रता* और *न्याय* के जो आदर्श अंकित हैं, वे इस परंपरा की आधुनिक व्याख्या हैं।

नैतिकता और नीति का एकीकरण (Integration of Ethics and Policy)

राजधर्म शासन के उस आयाम की ओर संकेत करता है जहाँ *Policy* और *Ethics* एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। *कौटिल्य, भर्तृहरि* और *तुलसीदास* — सभी ने इस तथ्य पर बल दिया कि नीति की सफलता तभी है जब वह धर्म के अनुरूप हो। समकालीन प्रशासनिक विमर्श में इसे *Ethical Governance* कहा जाता है। *United Nations (1997)* ने सुशासन के आठ स्तंभों में *Moral Accountability* को प्रमुख स्थान दिया है। यह दृष्टिकोण बताता है कि शासन का लक्ष्य केवल *efficiency* नहीं, बल्कि *legitimacy* भी है।

राजधर्म की आधुनिक पुनर्प्रासंगिकता

आधुनिक भारत में जब शासन-प्रणाली पर भ्रष्टाचार, सत्ता-केंद्रिकता और नीतिनिर्माण में नैतिक पतन के आरोप लगते हैं, तब *राजधर्म* की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है।

राजधर्म शासन को आत्मसंयम, नैतिक विवेक और लोककल्याण की दिशा में पुनर्स्थापित करने का आग्रह करता है। यह विचार *महात्मा गांधी, विनोबा भावे* और *जयप्रकाश नारायण* जैसे नेताओं के राजनीतिक दर्शन में भी स्पष्ट दिखता है। उनके लिए राजनीति *सेवा* थी, *सत्ता* नहीं। *राजधर्म* शासन को इसी लोकमंगल के केंद्र में रखता है — जहाँ जनता, न कि शासक, सर्वोच्च होती है। यदि आधुनिक *Good Governance* को भारतीय संदर्भ में नैतिक आधार देना है, तो *राजधर्म* की पुनर्पाठित अवधारणा ही उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यह शासन को *Moral Humanism* की दिशा में ले जाती है, जहाँ नीति और मूल्य दोनों एक साथ कार्य करते हैं।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में *'राजधर्म'* केवल शासन की एक संकल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत नैतिक दर्शन है जो सत्ता को लोकमंगल से जोड़ता है। इस शोध के समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि *'राजधर्म'* और आधुनिक *'Good Governance'* दोनों ही सत्ता के औपचारिक ढाँचे से आगे बढ़कर नैतिक शासन (*Ethical Governance*) की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। राजधर्म की मूल भावना यह है कि शासन का उद्देश्य केवल स्थायित्व, शक्ति-संचय या नीतिगत परिणाम नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण (*Public Welfare*) और धर्म की स्थापना (*Moral Order*) है। यही दृष्टिकोण आज के सुशासन की आत्मा में समाहित है, जो प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी, और सहभागी बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है (Maheshwari, 2018)।

राजधर्म का ऐतिहासिक और दार्शनिक पुनर्पाठ

राजधर्म की जड़ें वैदिक और उत्तरवैदिक परंपरा में गहराई तक पैठी हुई हैं। *मनुस्मृति, महाभारत* और *अर्थशास्त्र* जैसे ग्रंथ इस बात पर बल देते हैं कि सत्ता का दायित्व केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा करना है। कौटिल्य ने राजा को *'धर्मपालक'* कहा है — "वह जो समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करे" (Arthashastra, Book I, Chapter 7)। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में प्रशासन एक *Spiritual Responsibility* के रूप में देखा जाता था, न कि मात्र *Political Functioning* के रूप में। *'राजधर्म'* का यह दार्शनिक दृष्टिकोण शासन को एक मानवीय और मूल्य-आधारित क्रिया के रूप में देखता है, जो आज की प्रशासनिक अवधारणा *Ethical Public Administration* से अत्यंत समीप है (Bhattacharya, 2008)।

सुशासन के नैतिक स्तंभ और भारतीय परंपरा

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि आधुनिक *'Good Governance'* की अवधारणा, जिसमें *Transparency, Accountability, Participation, Equality* और *Justice* जैसे मूल्य निहित हैं, भारतीय *'राजधर्म'* के ही व्यावहारिक रूप हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP, 1997) ने सुशासन के आठ मूल स्तंभों को परिभाषित किया था — *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness, Accountability*। यदि इन सभी को भारतीय परंपरा के

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

आलोक में देखा जाए, तो वे राजधर्म के मूल सिद्धांत — धर्म, नीति, लोकसंग्रह और न्याय — से समानता रखते हैं।

समकालीन शासन और राजधर्म की पुनर्प्रासंगिकता

वर्तमान युग में, जब राजनीति अक्सर नैतिकता से विमुख होती जा रही है, *राजधर्म* का पुनर्पाठ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली भले ही *Managerial, Technical* और *Procedural* हो, परंतु यदि उसमें नैतिक विवेक (*Moral Consciousness*) और सार्वजनिक उत्तरदायित्व (*Public Accountability*) का समावेश नहीं होगा, तो शासन केवल यांत्रिक रह जाएगा।

भारत में प्रशासनिक सुधारों की चर्चा — जैसे *Right to Information Act (2005)*, *Citizen's Charter*, *e-Governance* और *Panchayati Raj Reforms* — सभी राजधर्मीय चेतना की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं। इन नीतियों का मूल उद्देश्य वही है जो प्राचीन भारत में था — जनसहभागिता के माध्यम से न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन की स्थापना।

नैतिक प्रशासन की आवश्यकता और राजधर्म का मार्गदर्शन

राजधर्म का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह राजनीति को नैतिक अनुशासन में बाँधता है। कौटिल्य ने शासन में *'Self-Discipline' (स्वयं अनुशासन)* को सर्वोपरि माना, जबकि तुलसीदास ने *रामराज्य* की कल्पना में धर्म पर आधारित नीति को सर्वोच्च बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में, जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग और नीतिनिर्माण में असमानता जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तब राजधर्म का यह सिद्धांत प्रशासन को पुनः *Ethical Foundation* प्रदान करता है।

राजधर्म यह सिखाता है कि शासन में नैतिकता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह शासन को *Human-Centric Morality* की दिशा में प्रेरित करता है, जहाँ नीतियाँ मानवीय संवेदना और नैतिक संतुलन से निर्मित हों।

भविष्य के प्रशासन के लिए राजधर्म की दिशा

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

राजधर्म और सुशासन का समन्वय भारतीय शासन की भविष्य दिशा के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है —

1. **Policy with Values** — नीतिनिर्माण में मूल्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे लोकनीतियाँ न्यायपूर्ण और समावेशी बनें।
2. **Ethical Local Governance** — पंचायत व नगर निगम जैसी संस्थाओं को नैतिक उत्तरदायित्व के प्रशिक्षण से सशक्त किया जाए।
3. **Civil Service Ethics** — सिविल सेवा प्रशिक्षण में *राजधर्म* के सिद्धांतों को सार्वजनिक नीति के नैतिक आधार के रूप में सम्मिलित किया जाए।
4. **Participatory Governance** — शासन में नागरिक सहभागिता को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए।

इन सबके माध्यम से शासन का स्वरूप *Power-Oriented Politics* से *Service-Oriented Governance* और *Management* से *Moral Inspiration* की ओर परिवर्तित हो सकता है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि *राजधर्म* केवल प्राचीन भारत का एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आज के लोकतांत्रिक शासन के लिए एक प्रासंगिक नैतिक रूपरेखा (*Contemporary Ethical Framework*) है। यह शासन को आत्मसंयम, उत्तरदायित्व और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन देता है।

राजधर्म का अंतिम संदेश यही है — **"सत्ता का मूल्य उसकी शक्ति में नहीं, उसके धर्म में है।"**

इसलिए, जब तक शासन के निर्णयों में *धर्म* (Morality) और *लोकसंग्रह* (Public Welfare) का संतुलन नहीं होगा, तब तक सुशासन का आदर्श अधूरा रहेगा। *राजधर्म* प्रशासन को इसी संतुलन की ओर ले जाने वाली वह परंपरा है, जो आज भी भारतीय शासन के लिए नैतिक दिशादर्शक के रूप में जीवित है।

References

Arthashastra of Kautilya. (1915). Translated by R. Shamasastry. Bangalore: Government Press.

Bhattacharya, Mohit. (2008). New Horizons of Public Administration. New Delhi: Jawahar Publishers.

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.118-128

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

Gandhi, M. K. (1909). Hind Swaraj or Indian Home Rule. Ahmedabad: Navajivan Press.

Mahabharata, Shanti Parva (Critical Edition). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.

Maheshwari, S. R. (2018). Indian Administration. New Delhi: Orient BlackSwan.

Manusmriti. (Trans. G. Bühler). (1886). The Laws of Manu. Oxford: Clarendon Press.

Nayyar, Deepa. (2022). Ethics and Governance in Digital India. New Delhi: Routledge.

Singh, S. K. (2010). Local Governance in India: Decentralization and Beyond. New Delhi: Sage Publications.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.

World Bank. (2002). Reforming Public Institutions and Strengthening Governance. Washington, D.C.: World Bank.

Constituent Assembly Debates. (1949). Vol. XI. New Delhi: Lok Sabha Secretariat.